दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-३४८ वा | शनिवार २६ जुलै २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

सऊदी अरब की चुपचाप रणनीति: फ्रांस ने दी फिलिस्तीन को मान्यता, इज़राइल को बड़ा झटका

रिपोर्ट: दिनानाथ परब ।

नई दिल्ली/

इज़राइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों में सुधार की कोशिशें चल ही रही थीं कि इसी बीच सऊदी अरब ने पर्दे के पीछे से एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। इज़राइल की नेतन्याहू सरकार के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि यूरोप का एक शक्तिशाली देश – फ्रांस – अब फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने जा रहा है। यह सऊदी अरब की कूटनीतिक रणनीति का परिणाम है और इससे आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तनाव और गर्माहट बढ़ सकती है।

फ्रांस ने अमेरिका और नेतन्याहू के विरोध को किया नजरअंदाज़

मिली जानकारी के अनुसार, फ्रांस ने इज़राइल और अमेरिका के विरोध को नजरअंदाज करते हुए फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के संकेत दिए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यह निर्णय सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुझाव पर लिया। यह सुझाव इस आधार पर दिया गया कि यदि फिलिस्तीन को मान्यता मिलती है, तो मध्य-पूर्व में जारी युद्ध को रोका जा सकता है।

सऊदी अरब की गुप्त कूटनीति

'अल-अरबिया' की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब ने जून २०२५ में इस मिशन की शुरुआत की थी। सऊदी क्राउन प्रिंस ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें समझाया कि १९६७ की सीमाओं के आधार पर विवाद सुलझ सकता है, जिसमें पूर्वी यरुशलम को

फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। फिलहाल पूर्वी यरुशलम इज़राइल के कब्जे में है।

सऊदी अरब दो-राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का नेतृत्व कर रहा है और इसी महीने के अंत में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी बैठक होने वाली है। सऊदी अरब की योजना है कि ब्रिटेन जैसे अन्य प्रभावशाली देशों को भी इस प्रस्ताव के समर्थन में लाया जाए।

फिलिस्तीन को क्या मिलेगा फायदा?

१. अंतरराष्ट्रीय मान्यता: फ्रांस की मान्यता मिलने से फिलिस्तीन एक आधिकारिक और स्वतंत्र देश बन जाएगा।

२. अपना सेना अधिकार: अब तक फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से सेना रखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन स्वतंत्र राष्ट्र बनने पर वह अपनी सैन्य व्यवस्था बना सकेगा।

३. हमास का समीकरण: फिलहाल 'हमास' को फिलिस्तीन की प्रॉक्सी सेना माना जाता है, जिसे कई देश आतंकवादी संगठन के रूप में देखते हैं। अब इस समीकरण में बदलाव आ सकता है।

बफर ज़ोन पर भी असर

इज़राइल ने गाज़ा और वेस्ट बैंक के कई हिस्सों को 'बफर ज़ोन' घोषित कर रखा है। यदि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलती है, तो इन क्षेत्रों पर उसका आधिकारिक दावा बन जाएगा।

इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इससे ईरान को एक और मौका मिलेगा कि वह इन क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाकर इज़राइल में आतंकवाद फैला सके।

फिलिस्तीन को फ्रांस द्वारा मिली यह समर्थन इज़राइल के लिए कूटनीतिक और सुरक्षा दोनों स्तरों पर गंभीर चुनौती है। वहीं सऊदी अरब ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन के लिए माहौल बनाकर एक चतुर और गुप्त खेल खेला है, जिसका असर आने वाले दिनों में और व्यापक रूप से दिख सकता है।

प्रचंड नेतृत्व विशाल कर्तृत्व...!

महाराष्ट्र का भाग्य, मिले दिग्गज...

पंकजाताई मुंडे साहेब के नाम के इर्द-गिर्द कितना और कैसा प्रभाव है, इसे न केवल पूरे महाराष्ट्र ने, बल्कि देश ने भी कई बार अनुभव किया है। मुंडे साहेब की बेटी के नाम में जो शक्ति है, वह ताई की प्रत्येक क्रिया में नजर आती है। गली से लेकर दिल्ली तक और चांद से बांद्रा तक, ना. पंकजाताई के प्रचंड नेतृत्व की गवाही आज पूरा महाराष्ट्र दे रहा है। नेतृत्व कैसा होना चाहिए और उससे कर्तृत्व कैसे उभरता है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण हैं ना. पंकजाताई मुंडे साहेब। संघर्ष कन्या, महाराष्ट्र की शेरनी और सर्वसामान्य जनता के मन में बसी लोकनेता के रूप में ताई साहेब ने जो ख्याति अर्जित की है, वह उनके कार्यकर्तृत्व को सिद्ध करने वाली है। संघर्ष और केवल संघर्ष, इन दो शब्दों की शक्ति से तपकर निकली इस नेतृत्व ने महाराष्ट्र को जीत लिया है। साहेब की बेटी से लेकर जनमान्य ताई तक, विभिन्न रूपों में पंकजाताई ने जो छलांग लगाई है, वह उनकी सामाजिक और राजनीतिक यात्रा में तडाखेबाज, निर्भीक सफलता कही जा सकती है। जीत-हार, सुख-दुख को पचाते हुए उसमें से रास्ता निकालते हुए ताई की यात्रा अवर्णनीय, अतुलनीय और अविश्वसनीय है। भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय कार्यकर्ता से लेकर राज्य के मंत्रीपद तक, अनेक भूमिकाओं में आगे बढ़ते हुए ताई साहेब ने विभिन्न पदों पर काम किया। इस दौरान उन्होंने सामान्य कार्यकर्ता और सामान्य व्यक्ति को केंद्र में रखकर सभी को समान सम्मान दिया। देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस के नेतृत्व में पंकजाताई ने पूरे महाराष्ट्र में चहुंमुखी विकास किया। लोकाभिमुख शासन कैसे किया जा सकता है, इसके लिए उनका हमेशा पहल रहा। कार्यकर्ता मेरा प्राण है और उस प्राण के लिए ही मैं हूं, यह विश्वास पंकजाताई के नेतृत्व ने पूरे महाराष्ट्र को दिया। एक लढवय्या नेता की तरह ताई साहेब परिस्थितियों से लड़ीं, उठूंगी नहीं, हारूंगी नहीं, लिया हुआ संकल्प छोडूंगी नहीं के अनुसार ताई ने हर बार समान न्याय की भूमिका रखी। सत्ता हो या न हो, वही ताकत और वही विश्वास देने का काम ताई साहेब ने महाराष्ट्र में किया। मुंडे साहेब के बाद ताई साहेब ने बीड जिले का नाम देश में पहुंचाया। इसलिए ही बेटी, पंकजा कहते हुए देश के नेता नरेंद्रभाई मोदी और अमित शाह ने कई बार ताई साहेब के सिर पर हाथ रखा। जिस मुंडे साहेब की बेटी को पूरे महाराष्ट्र की जनता ने तलवे पर फोडे की तरह संभाला, उसी ताई साहेब के सिर पर पार्टी नेतृत्व ने हाथ रखकर ताकत दी। वही ताकत आज मंत्रिपद के रूप में महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए कार्यरत है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस और ताई साहेब के नेतृत्व में एक नया महाराष्ट्र बन रहा है, यह वास्तव में गर्व की बात है। देश के दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की काव्य पंक्तियों के अनुसार...

मैं हमेशा से ही वादे
लेकर नहीं आया,
इरादे लेकर आया हूं...!

ये पंक्तियां ताई साहेब के मजबूत इरादों पर मुहर लगाने वाली हैं। राज्य की पर्यावरण और पशुसंवर्धन मंत्री के रूप में पंकजाताई की राजनीतिक यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती रहे और उनके हाथों महाराष्ट्र की जनता की निरंतर सेवा होती रहे, यही शुभकामना।

ताई साहेब को जन्मदिन की अनंत कोटि शुभकामनाएं...!

सलीम जहांगीर
प्रदेश महामंत्री
भाजपा, अल्पसंख्यक मोर्चा
महाराष्ट्र राज्य

बीड विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण कार्यों को लेकर डॉ. योगेश क्षीरसागर की सीईओ से चर्चा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान से जिला परिषद कार्यालय में मुलाकात

बीड (प्रतिनिधि), २५ जुलाई:

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीड विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगेश क्षीरसागर ने शुक्रवार (२५ जुलाई) को बीड जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान से मुलाकात की। इस बैठक में बीड विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण भागों में लंबित और प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति, सड़क विकास, स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाएं और जिला परिषद के माध्यम से चल रही योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। डॉ. योगेश क्षीरसागर ने कहा कि नागरिकों को तात्कालिक सुविधा देने के लिए प्रशासन को और अधिक सक्रियता से कार्य करना चाहिए।

इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं नालवंडी के सरपंच एडवोकेट राजेंद्र राऊत, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष शुभम कातांगले, विठ्ठल गुजर सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अन्य सरपंच उपस्थित थे।

पंकजाताई मुंडे के जन्मदिन पर शेख फाउंडेशन और समाज कल्याण न्यास की ओर से 'पसायदान' के अनाथ व जरूरतमंद बच्चों को अन्नदान

वृक्षारोपण कर मनाया गया जन्मदिन

बीड (प्रतिनिधि):

पशुपालन और पर्यावरण मंत्री पंकजाताई मुंडे के जन्मदिन के अवसर पर शेख फाउंडेशन और समाज कल्याण न्यास की संयुक्त पहल से ढेकणमोह स्थित पसायदान सेवा प्रकल्प में रहने वाले अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को अन्नदान किया गया। साथ ही परिसर में वृक्षारोपण और बच्चों को शैक्षणिक सामग्री का वितरण भी किया गया।

शेख फाउंडेशन और समाज कल्याण न्यास द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी सामाजिक उपक्रम के तहत पसायदान सेवा प्रकल्प में यह आयोजन किया गया। पिछले १५ वर्षों से पंकजाताई मुंडे के जन्मदिन पर वहां के बच्चों को शैक्षणिक सामग्री और भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

इस वर्ष भी २६ जुलाई को ढेकणमोह स्थित पसायदान सेवा प्रकल्प की बेटियों के हाथों केक काटकर पंकजाताई मुंडे का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को एक दिन का अन्नदान भी किया गया।

कार्यक्रम में भाजपा नेता शेख फारुख, बाबुराव खाडे, एडवोकेट विनोद जायभाये, पत्रकार अशोक खाडे, गोरख मुंडे, गणेश दराडे, डॉ. डिगे, शिवाजी चाटे, मतीन बागवान, संदीप अदमाने, रमेश कदम, इलियास पठान, पप्पू तावरे, मुबारक शेख और पसायदान के संचालक गोवर्धन दराडे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर वृक्षारोपण और शैक्षणिक सामग्री का वितरण भी किया गया।

मोहन भागवत- मुस्लिम उलेमाओं की मुलाकात: सांप्रदायिक सौहार्द की दिशा में एक सकारात्मक कदम

भारत, अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के लिए विश्व भर में जाना जाता है, समय-समय पर सामाजिक और धार्मिक तनावों का सामना करता रहा है। इन तनावों को कम करने और समाज में आपसी समझ और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए संवाद और सहयोग की आवश्यकता होती है। बीती २४ जुलाई को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने राजधानी के हरियाणा भवन में ५० से अधिक प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं और विद्वानों के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात की।

इस बैठक का आयोजन अखिल भारतीय इमाम संगठन (एआईआईओ) के प्रमुख मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने किया था। यह मुलाकात, जो लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली, हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच की खाई को पाटने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम मानी जा रही है। इस लेख में इस मुलाकात के महत्व, इसके संभावित प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी।

मुलाकात का संदर्भ और उद्देश्य

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), जिसे भारत में हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के रूप में जाना जाता है, और मुस्लिम समुदाय के बीच संवाद का इतिहास हाल के वर्षों में उभर कर सामने आया है। यह मुलाकात २०२२ के बाद आरएसएस प्रमुख की मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ दूसरी बड़ी पहल थी। इससे पहले, सितंबर २०२२ में, मोहन भागवत ने नई दिल्ली में एक मस्जिद और मदरसे का दौरा किया था और मौलाना उमेर इलियासी के साथ मुलाकात की थी। उस समय, मौलाना इलियासी ने भागवत को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, जो राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

२४ जुलाई २०२५ की बैठक में आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं, जैसे संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल, राम लाल और इंद्रेश कुमार, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) के प्रमुख हैं, ने भी हिस्सा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक, मुस्लिम पक्ष से गुजरात और हरियाणा के मुख्य इमाम, उत्तराखंड, जयपुर और उत्तर प्रदेश के ग्रैंड मुफ्ती, दारुल उलूम देवबंद और नदवा जैसे प्रमुख इस्लामी संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य संवाद को बढ़ावा देना था, जैसा कि मौलाना इलियासी ने कहा, हमारा प्राथमिक लक्ष्य संवाद की भावना को जीवित रखना है। हम अलग-अलग धर्मो का पालन कर सकते हैं, लेकिन हम सभी भारतीय हैं। समुदायों के बीच कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के संचार मंच को जारी रखना चाहिए।

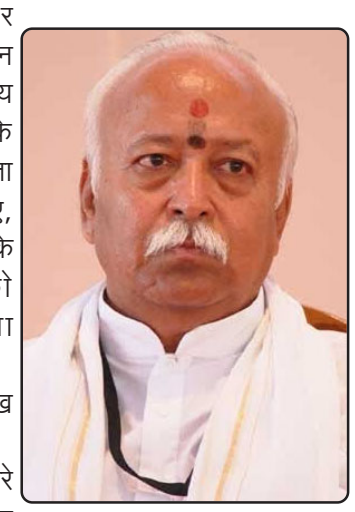

चर्चा के प्रमुख बिंदु

इस बंद कमरे की बैठक में राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सह-अस्तित्व और सामाजिक सौहार्द जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक किसी एक विवादास्पद मुद्दे, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद या हिजाब विवाद, तक सीमित नहीं थी। इसके बजाय, इसने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुकुलों और मदरसों के बीच संवाद को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया।

लेखक
विवेक शुक्ला
दिल्ली

मौलाना इलियासी ने बताया कि इस बैठक में यह सहमति बनी कि मंदिरों के पुजारी और मस्जिदों के इमाम, साथ ही गुरुकुलों और मदरसों के बीच नियमित संवाद होना चाहिए ताकि आपसी गलतफहमियां दूर हो सकें और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिले।

मोहन भागवत ने इस दौरान राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया और कहा कि हम सभी एक ही नाव में सवार हैं-अगर हम डूबे, तो एक साथ डूबेंगे। यह बयान भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता को एकजुट रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आरएसएस और मुस्लिम समुदाय के बीच विश्वास निर्माण के लिए इस तरह के संवाद निरंतर जारी रहेंगे।

सकारात्मक प्रभाव की संभावनाएं

इस मुलाकात का सकारात्मक प्रभाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है। सबसे पहले, यह दोनों समुदायों के बीच विश्वास निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में हाल के वर्षो में धार्मिक ध्रुवीकरण और तनाव की घटनाओं ने सामाजिक एकता को प्रभावित किया है। ऐसे में, आरएसएस जैसे प्रभावशाली संगठन और मुस्लिम धर्मगुरुओं का एक मंच पर आना एक सकारात्मक संदेश देता है। यह संदेश न केवल शीर्ष स्तर पर, बल्कि जमीनी स्तर पर भी सौहार्द को बढ़ावा दे सकता है।

दूसरा, इस बैठक ने धार्मिक नेताओं की भूमिका को रेखांकित किया। मौलाना इलियासी ने कहा कि धार्मिक नेता समाज में प्रभावशाली होते हैं, और उनके बीच संवाद सामाजिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मंदिरों और मस्जिदों, गुरुकुलों और मदरसों के बीच नियमित संचार से गलतफहमियां कम हो सकती हैं, जो सामाजिक एकता के लिए आवश्यक है।

तीसरा, यह मुलाकात उस समय हुई जब भारत में सामाजिक और धार्मिक तनावों को लेकर सिविल सोसाइटी और विपक्ष की ओर से आलोचनाएं हो रही हैं। इस संदर्भ में, यह बैठक एक जवाब के रूप में देखी जा सकती है, जो यह दर्शाती है कि आरएसएस सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएसएस को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का वैचारिक मार्गदर्शक माना जाता है।

चुनौतियां और आलोचनाएं

हालांकि यह मुलाकात सकारात्मक है, लेकिन इसे लेकर कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं। २०२२ में हुई ऐसी ही एक मुलाकात के बाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) और जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे संगठनों ने कहा था कि मौलाना इलियासी का मुस्लिम समुदाय में पर्याप्त प्रभाव नहीं है। कुछ ने इसे प्रतीकात्मक या खोखला कदम बताया था, क्योंकि आरएसएस ने उन मुस्लिम संगठनों से संपर्क नहीं किया जिनका समुदाय में व्यापक प्रभाव है। इसके अलावा, कुछ आलोचकों का मानना है कि ऐसी बैठकों में ठोस मुद्दों, जैसे मस्जिद-मंदिर विवाद या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा, पर खुलकर चर्चा नहीं होती।

भविष्य की संभावनाएं

मौलाना इलियासी ने इस मुलाकात को निरंतर संवाद की शुरुआत बताया है, और मोहन भागवत ने भी इस विचार का समर्थन किया है। यह संकेत देता है कि भविष्य में ऐसी और बैठकें हो सकती हैं, जो सामाजिक सौहार्द को और मजबूत करेंगी। इसके अलावा, यह मुलाकात उस समय हुई जब आरएसएस अपनी शताब्दी मना रहा है और एआईआईओ अपनी ५०वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह एक प्रतीकात्मक अवसर है, जो दोनों पक्षों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मशहूर लेकक फिरोज अहमद बख्त कहते हैं कि मोहन भागवत और मुस्लिम उलेमाओं की यह मुलाकात भारत के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल धार्मिक समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द के लिए एक मॉडल भी प्रस्तुत करता है। हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह संवाद जमीनी स्तर तक पहुंच पाता है और क्या यह ठोस मुद्दों को हल करने में सक्षम होता है। यदि यह प्रयास निरंतर और समावेशी रहा, तो यह भारत की बहुलवादी संस्कृति को और मजबूत कर सकता है।

किसे सुनाऊँ उर्दू ज़बान का हाल!

आप भी सोच रहे होंगे कि आज हम किस बेबसी में फंसकर ऐसी बात कह रहे हैं। दरअसल, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं लोगों से उर्दू ज़बान और साहित्य पर बातचीत करता हूँ, तो मुझे लोगों में काफी निराशा दिखाई देती है। सोचा, क्यों न आज हम उर्दू ज़बान और साहित्य के बारे में अपना नज़रिया पेश करें।

हालांकि, मुझे लगता है कि इस छोटे से कॉलम में पूरी बात को समेटना असंभव है। हाँ, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया, तो मैं ऐसे लेख लिखता रहूँगा ताकि पाठकों की बेबसी और निराशा का कोई हल निकल सके। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है, जहाँ रोज़ाना ऐसी ख़बरें नज़रों से गुज़रती हैं, जो कभी तो ज्ञान बढ़ाती हैं, और कभी-कभी ऐसी ख़बरें सुनकर या वीडियो देखकर दिमाग उलझ जाता है। मिसाल के तौर पर, रोज़ाना नए-नए शायरों और बुद्धिजीवियों से परिचय होता है, और ऐसी शायरी और कथन सुनने को मिलते हैं कि लगता है, हम तो किसी ऐसे द्वीप में रह रहे हैं, जहाँ अब तक इन शायरों और बुद्धिजीवियों को जान ही नहीं पाए।

हाल ही में एक साहब का पोस्ट नज़र से गुज़रा, जिसमें लिखा था, फलाँ साहब (जिनका नाम मैंने पहली बार सुना, यह मेरी कमज़ोरी है) की किताब के लेखक के सामने शब्द हाथ बाँधे खड़े रहते हैं और वे चाहते हैं कि उनका चयन किया जाए। यह अहम बात एक एसोसिएट प्रोफेसर ने उनकी किताब के विमोचन के मौके पर अपने भाषण में कही। जब लोगों ने मुझे बताया, तो मेरा भी सिर झुक गया। लेकिन मेरा मानना है कि उर्दू ज़बान में ऐसे अनगिनत शब्द हैं, जिनके बिना हमारी लेखनी विश्वसनीय नहीं हो सकती। इसीलिए हम शब्दों के सामने हाथ बाँधे रहते हैं, क्योंकि ये शब्द आपसी सम्मान और रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं, और यही शब्दों और लेखनी का रिश्ता हमारी रचनाओं को प्रभावशाली बनाता है।

अब इसे हमारी बदकिस्मती कहें कि पिछले बारह सालों से मैंने शायरी शुरू की, और अब भी सिर तब झुक जाता है, जब कोई पूछता है कि क्या आपने दुबई में मुशायरा पढ़ा है। इससे मुझे लगा कि जैसे एक मुसलमान के लिए हज और उमरा के लिए मक्का जाना ज़रूरी है, वैसे ही आजकल एक शायर को प्रमाणपत्र लेने के लिए दुबई का चक्कर लगाना भी ज़रूरी है। बस, दिक्कत यह है कि मुझे खुशामद या नाटकबाज़ी नहीं आती, और सारी कोशिशों के बावजूद मैं अब तक नाकारा हूँ। वैसे, अपनी शायरी पर यकीन है कि इंशाल्लाह एक दिन हम भी दुबई जाएँगे। हालाँकि, मैं दुबई में कई बार घूम चुका हूँ, और वहाँ मुशायरों के साथ-साथ ऐसी सजावट और सुविधाएँ हैं कि अल्लाहु अकबर। मुझे तो लंदन की पश्चिमी और आज़ाद ज़िंदगी, दुबई की चमक-दमक और ऐय्याशी के सामने फीकी लगती है।

उर्दू एक खूबसूरत, मधुर और सभ्य ज़बान है, जो सदियों से उपमहाद्वीप के लोगों के दिलों को जोड़ती और प्यार बिखेरती आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसकी नींव फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी और स्थानीय भाषाओं के मिश्रण से बनी, जिसने इसे एक विश्वव्यापी और सर्वग्राही भाषा बना दिया। यहाँ मैं यह भी बता दूँ कि दुनिया भर में उर्दू के प्रचार में उपमहाद्वीप के उन बुद्धिजीवियों, शायरों और साहित्यकारों का उल्लेखनीय योगदान रहा है, जिन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को दूसरे देशों में पहचान दिलाई और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उर्दू साहित्य ने न केवल भाषा के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि सभ्यता, नैतिकता और बौद्धिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया। लेकिन आज उर्दू ज़बान और साहित्य कई समस्याओं का शिकार है, जिन्हें नज़रअंदाज़ करना उर्दू के पतन का कारण बन सकता है। मिसाल के तौर पर, शैक्षणिक संस्थानों में उर्दू की उपेक्षा हो रही है। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में उर्दू को वह महत्व नहीं दिया जा रहा, जो एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसे मिलना चाहिए। ज़्यादातर संस्थान अंग्रेज़ी या स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उर्दू की शिक्षा का स्तर कमज़ोर है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अंग्रेज़ी या स्थानीय भाषाओं का रुझान बढ़ गया है, जिससे उर्दू कमज़ोर हो रही है। हालाँकि, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मदरसों ने उर्दू के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो दुर्भाग्य से राजनीतिक, धार्मिक और भेदभाव का शिकार हो रहे हैं।

डिजिटल दुनिया में मीडिया और तकनीक में उर्दू की मौजूदगी कम होती जा रही है। ज़्यादातर डिजिटल सामग्री अंग्रेज़ी में होती है, जिससे नई पीढ़ी उर्दू से दूर होती जा रही है। एक बेहतरीन मिसाल यह है कि अगर आप सोशल मीडिया पर उर्दू शायरी का पोस्ट देखें, तो ज़्यादातर पोस्ट आपको हिंदी या रोमन में लिखे मिलेंगे, जिससे पता चलता है कि उर्दू पढ़ने वालों की संख्या कम होती जा रही है। गैर-मियारी भाषा का प्रचार एक चिंता की बात है। मीडिया, खास तौर पर टीवी ड्रामों और फिल्मों में गैर-मियारी उर्दू और बोलचाल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो भाषा की मूल संरचना को प्रभावित कर रहा है। मिसाल के तौर पर, आजकल लोग खूबसूरत को खूबसूरत कहते हैं, जो सुनने में काफी बुरा लगता है। एक और समस्या यह है कि उर्दू साहित्य में पढ़ने की कमी है। नई पीढ़ी में उर्दू साहित्य पढ़ने का रुझान कम हो गया है। क्लासिकल साहित्य को बोझिल समझा जाता है, और आधुनिक साहित्य को नज़रअंदाज़ किया जाता है। इसकी मिसाल यह है कि आजकल हर कोई वीडियो देख रहा है, जहाँ लोग ग़ालिब, मीर और इकबाल की शायरी को अपने नाम से पढ़कर रातोंरात मशहूर हो रहे हैं। साहित्यिक संस्थानों की कमज़ोरी और अक्षमता के कारण, उर्दू के प्रचार के लिए बने संस्थान या तो निष्क्रिय हैं या संसाधनों की कमी का शिकार हैं। साहित्यकारों को सरकारी स्तर पर वह स्वीकृति नहीं मिल रही, जिसके वे हकदार हैं। साहित्य के लिए साहित्य की जगह साहित्य के लिए व्यापार ने ले ली है। कुछ लेखक और प्रकाशक केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिखते हैं, जिससे साहित्य का स्तर प्रभावित होता है।

ये बातें तो उर्दू ज़बान और साहित्य की समस्याओं की थीं, तो इसका क्या हल निकाला जाए? मेरा मानना है कि पाठ्यक्रम में उर्दू को अनिवार्य स्थान देना चाहिए। सभी शिक्षण संस्थानों में उर्दू को अनिवार्य और प्रभावी ढंग से पढ़ाया जाए। पाठ्यक्रम को रोचक और आधुनिक समय के अनुरूप बनाया जाए। डिजिटल मंचों पर उर्दू को बढ़ावा देना चाहिए। उर्दू वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया मंच बनाए जाएँ ताकि नई पीढ़ी उर्दू में रुचि ले। साहित्यिक मेलों और प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए, लेकिन रेख्ता और दुबई के इवेंट आयोजकों की तरह नहीं, जो उर्दू का व्यावसायिक उपयोग करते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उर्दू की साहित्यिक प्रतियोगिताएँ, मुशायरे और नाटक आयोजित किए जाएँ ताकि छात्रों में रुचि बढ़े।

एक सफह (Page)
फहीम अख्तर लंदन के नाम

यहाँ मैं भारत के बचपन ग्रुप और इसके संस्थापक सिराज अज़ीम, जो दिल्ली से हैं, का ज़िक्र करना चाहूँगा, जो बच्चों के साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उर्दू अकादमियों और साहित्यिक संगठनों को सरकारी सहायता बढ़ानी चाहिए ताकि वे उर्दू ज़बान और साहित्य के प्रचार के लिए बेहतर काम कर सकें। इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी के संरक्षक जनाब नदीम-उल-हक की मैं सराहना करूँगा, जिनके संरक्षण में अकादमी काफी काम कर रही है। उर्दू साहित्य को समकालीन विषयों से जोड़ना चाहिए। साहित्यकारों को चाहिए कि वे आधुनिक मुद्दों पर लिखें ताकि नई पीढ़ी उर्दू साहित्य को अपने हालात से जुड़ा हुआ महसूस करे। आज हमने उर्दू ज़बान और साहित्य पर संक्षेप में कॉलम लिखकर उन समस्याओं को उजागर किया है, जो आम लोगों की समस्याएँ हैं। उर्दू ज़बान और साहित्य हमारा सांस्कृतिक विरासत है, जिसकी हिफाज़त और प्रचार हम सबकी ज़िम्मेदारी है। अगर हमने आज उर्दू को नहीं संभाला, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ नहीं करेंगी। हमें चाहिए कि हम उर्दू को सिर्फ़ एक ज़बान न समझें, बल्कि अपनी पहचान का हिस्सा मानकर इसे बढ़ावा दें। यही उर्दू के भविष्य की गारंटी है। तो आइए, हम यह संकल्प लें कि हम अपने-अपने तरीके से उर्दू के प्रचार के लिए काम करते रहेंगे। उर्दू ज़िंदाबाद, उर्दू पायंदाबाद।

फहीम अख्तर, लंदन

कैम्ब्रिज में पहली 'इको-फ्रेंडली' मस्जिद और फैज़ का निकाह

ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं, जो न केवल दिल को छू लेते हैं, बल्कि हमेशा के लिए यादों में अमर हो जाते हैं। डॉ. फैज़ जब्बार की शादी की रस्म भी ऐसे ही लम्हों में से एक थी, जो कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद में आयोजित हुई।

उस दिन की रूहानियत, खुशी और अपनापन ने एक गहरा असर छोड़ा। मेरे दोस्त और भारत के झारखंड राज्य से ताल्लुक रखने वाले शाहिद जब्बार भाई, जो पेशे से ब्रिटिश सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट हैं और पिछले चालीस साल से लंदन के ब्रोमली इलाके में रहते हैं, उन्होंने शनिवार, ५ जुलाई को अपने होनहार बेटे डॉ. फैज़ जब्बार के निकाह में शामिल होने की दावत दी और मुझसे एक सेहरा पढ़ने की गुज़ारिश भी की।

लंदन का मौसम आज बहुत सुहावना था। हल्की-हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो शरीर को ताज़गी दे रही थी, और साथ ही हल्की धूप ने माहौल को रौशन और सुकून भरा बना दिया था। सुबह नौ बजे घर से निकला और बस से बीस मिनट बाद मॉडर्न स्टेशन पहुँचा, जहाँ से हम लंदन अंडरग्राउंड में सवार होकर बीस मिनट बाद टॉटेनहम रोड स्टेशन पहुँचे। टॉटेनहम रोड स्टेशन से एलिज़ाबेथ लाइन की ट्रेन पकड़कर पचास मिनट की यात्रा के बाद हम सात किंग्स स्टेशन पहुँचे और थोड़ी देर चलने के बाद अपने दोस्त तारिक बर्नी के घर पहुँच गए। फिर हम तारिक बर्नी और उनकी पत्नी के साथ उनकी बीएमडब्ल्यू गाड़ी में सवार होकर एक घंटे दस मिनट में कैम्ब्रिज पहुँच गए।

फैज़ को दूल्हे के रूप में देखना एक भावनात्मक पल था। जिस आत्मविश्वास, सुकून और खुशी के साथ वह बैठा था, वह एक नई ज़िंदगी के स्वागत का प्रतीक था। जैसे ही मस्जिद के आँगन में कदम रखा, एक सुकून और रूहानी हवा ने हमारा स्वागत किया। कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद अपनी खूबसूरती और रूहानी माहौल के लिए मशहूर है, और उस दिन तो वह और भी रौशन हो गई थी। निकाह की रस्म से पहले हर चेहरा मुस्कुराहटों से जगमगा रहा था। रिश्तेदार, दोस्त और मस्जिद का नूरानी माहौल, सब मिलकर एक प्यार भरी हवा बुन रहे थे। निकाह ब्रिटेन की मशहूर कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद के इमाम साहब ने पढ़ाया। निकाह का खुतबा, जिसमें प्यार, रहम और पति-पत्नी के रिश्ते की बुनियादों पर रोशनी डाली गई, दिल को छू गया। दिल ही दिल में दुआएँ निकलती रहीं कि अल्लाह ताला इन दोनों को अपनी रहम के साए में रखे और उनके रिश्ते को उम्र भर प्यार से भर दे।

निकाह के बाद शाहिद भाई ने हमारा परिचय मेहमानों से कराया और हमसे सेहरा सुनाने की गुज़ारिश की। मेहमानों ने सेहरा सुना, जिसे सुनकर नई और पुरानी पीढ़ी के लोग खूब आनंदित हुए। हर चेहरे पर मुस्कान थी और आँखों में एक चमक, जैसे उर्दू की मिठास दिलों को छू गई हो। बुजुर्गों को अपने बीते दिन याद आ गए, जबकि युवाओं ने पहली बार उर्दू के इस खूबसूरत रंग को दिल से महसूस किया। उस पल ऐसा लगा जैसे भाषा का रिश्ता पीढ़ियों को जोड़ रहा हो, और हर दिल बेकरार उर्दू की मिठास के सामने झुक गया हो, और उर्दू का सिर गर्व से ऊँचा हो गया हो। उस वक्त मुझे यह भी महसूस हुआ कि उर्दू सिर्फ़ एक ज़बान नहीं, बल्कि एक एहसास है, जो दिलों को जोड़ता है, यादों को जगाता है और संस्कृति का आइना बनकर सब पर छा जाता है।

ब्रिटेन के ऐतिहासिक शहर कैम्ब्रिज, जिसे विश्वविद्यालयों का शहर भी कहा जाता है, यहाँ ५ दिसंबर २०१९ को ब्रिटेन और यूरोप की पहली 'इको-फ्रेंडली' यानी पर्यावरण के अनुकूल मस्जिद बनाई गई, जो कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद के नाम से मशहूर है। यह मस्जिद पर्यावरणीय दृष्टि से पूरी तरह से टिकाऊ होने के कारण वैश्विक ध्यान आकर्षित कर चुकी है। २३ मिलियन ब्रिटिश पाउंड की लागत से बनी इस मस्जिद को बारह साल में पूरा किया गया। इसके आर्किटेक्ट ने कहा था कि यह मस्जिद २१वीं सदी में 'इस्लाम का सांस्कृतिक' पुल साबित होगी। लगभग ६००० कैम्ब्रिज के मुसलमान, जो मुश्किल से निजी आवासों, छोटी-छोटी मस्जिदों और भीड़भाड़ वाले इस्लामिक सेंटरों में नमाज़ अदा करते थे, उन्हें पार्किंग से लेकर कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए कैम्ब्रिज शहर में एक बड़ी मस्जिद की सख्त ज़रूरत थी। हालाँकि, मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए कैम्ब्रिज के मुसलमानों को लंबा इंतज़ार करना पड़ा और कई समस्याओं से जूझना पड़ा। इतनी बड़ी मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण एक बड़ी समस्या थी। इसके बाद मस्जिद की निर्माण के लिए भारी-भरकम राशि की भी ज़रूरत थी। लेकिन सबसे बड़ी बाधा शहर के बीचों-बीच इतनी बड़ी मस्जिद बनाने का विरोध था। वैसे भी, ब्रिटेन में घर हो या मस्जिद, विरोध होना आम बात है। ब्रिटेन में शिकायत करना और उस पर अमल करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। २०११ में कुछ अज्ञात लोगों ने, जो मस्जिद के पास ही रहते थे, पर्चे बाँटे, जिनमें मस्जिद निर्माण का कड़ा विरोध किया गया था। इसमें लिखा था कि मस्जिद के निर्माण से भीड़ होगी और उनका सुकून छिन जाएगा। इसके अलावा, लोगों को यह भी चिंता थी कि मस्जिद बहुत ऊँची बनेगी। कानून के मुताबिक, कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल ने सभी की बात सुनी। काउंसिल के मुताबिक, मस्जिद के विरोध में ५० शिकायतें मिलीं, जबकि इसके समर्थन में २०० पत्र मिले। आखिरकार, काउंसिल ने मस्जिद निर्माण की अनुमति दे दी।

इस मस्जिद में एक साथ १००० नमाज़ी नमाज़ अदा कर सकते हैं। इसके भूमिगत कार पार्क में ८२ गाड़ियाँ और ३०० साइकिलें खड़ी करने की जगह है। मस्जिद में पारंपरिक गुंबद तो हैं, लेकिन कोई मीनार नहीं बनाई गई है। आसपास रहने वालों का खयाल रखते हुए मस्जिद के बाहर अज़ान या किसी तरह के खुतबे की आवाज़ नहीं जाती। मस्जिद में लगी ईंटें कैम्ब्रिज जैसे ऐतिहासिक शहर की इमारतों से मिलती-जुलती हैं। इसमें सुलेख का काम तुर्की के मशहूर सुलेखक से करवाया गया है।

दिलचस्प बात यह है कि जब कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद का डिज़ाइन पेश किया गया, तो ट्रस्टीज़ ने इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि यह मस्जिद जैसा नहीं लगता। लेकिन मस्जिद के ट्रस्ट के चेयरमैन अपने फैसले पर अड़े रहे और डिज़ाइन में कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया। इस अनोखी मस्जिद को बनाने वाले आर्किटेक्ट्स पुरस्कार विजेता डेविड मार्क्स और उनकी पार्टनर जूलिया बारफील्ड हैं। दुर्भाग्य से, मार्क्स अपनी इस उत्कृष्ट कृति को पूरा होने के बाद देखने से पहले ही दुनिया से चले गए। अब कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद को यूरोप की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक माना जा रहा है, जो विश्वविद्यालयों के ऐतिहासिक शहर कैम्ब्रिज के शान के अनुरूप है। लोग कहते हैं कि यह मस्जिद कैम्ब्रिज शहर के लिए एक शानदार तोहफा है। मस्जिद के निर्माण के पीछे मुख्य प्रेरणा मशहूर गायक 'कैट स्टीवंस' हैं, जिन्होंने कई साल पहले इस्लाम अपनाकर यूसुफ इस्लाम नाम लिया, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर और मशहूर स्कॉलर डॉ. टिम विंटर हैं। यूसुफ इस्लाम ने मस्जिद निर्माण के लिए चंदा जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके लिए वे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन से भी मिले थे।

डॉ. टिम विंटर ने कहा था कि कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद सबके लिए होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लाम प्राकृतिक पर्यावरण का सम्मान करता है और चीज़ों के अपव्यय और बर्बादी को रोकता है। मस्जिद के निर्माण में इन बातों का खास खयाल रखा गया है। मिसाल के तौर पर, मस्जिद के बाहर एक खूबसूरत बगीचा बनाया गया है, जिसमें कोई भी समय बिता सकता है। इस बगीचे को मस्जिद में वज़ू के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी से सींचा जाता है। इसके अलावा, बारिश के पानी का दोबारा उपयोग करने का भी खास खयाल रखा गया है। इसकी छत इस तरह बनाई गई है कि पूरे साल रोशनी अंदर आती रहे, ताकि बिजली का कम इस्तेमाल हो। स्विटज़रलैंड से लाई गई लकड़ी ने मस्जिद की खूबसूरती को और बढ़ाया है। मस्जिद में लकड़ी के स्तंभ पेड़ों की तरह बनाए गए हैं, जो ऊपर जाकर छत के साथ जुड़ते हैं और एक 'कैनोपी' जैसा बनाते हैं, जो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के जुड़ाव का प्रतीक लगता है।

दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है और जलवायु और पर्यावरण से प्रभावित हो रही है, उस हिसाब से कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। मैं कैम्ब्रिज के मुसलमानों को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें यूरोप की पहली पर्यावरण के अनुकूल मस्जिद नसीब की, जिसकी आज ज़रूरत है।

फहीम अख्तर, लंदन

नोबेल शांति पुरस्कार और मियाँ ट्रम्प की ख्वाहिश

पुरस्कार एक ऐसा शब्द है, जिसे सुनकर हर किसी को दिली खुशी होती है, चाहे वह पुरस्कार पाने वाला हो या देने वाला। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब कोई अपनी कला या क्षमता का प्रदर्शन करता है, तो उसे उसकी विशेषता और योग्यता के लिए पुरस्कार से नवाज़ा जाता है।

बचपन में हमने ऐसी कई कहानियाँ पढ़ी थीं कि फलाँ बादशाह या रानी ने किसी आम इंसान को उसकी बहादुरी के लिए इनाम दिया। अलग-अलग देशों में तरह-तरह के इनाम और पुरस्कार दिए जाने का रिवाज आज भी कायम है। यूनान में ओलंपिक जीतने वालों को पत्तियों से सजा हुआ ताज पहनाने की परंपरा अब भी बरकरार है। कुछ देशों में पत्थरों पर लिखी तहरीर को पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। कई देशों में सैनिकों को बहादुरी के लिए कंधे पर कांस्य के मेडल लगाए जाते हैं।

इस तरह प्राचीन काल से पुरस्कारों का सिलसिला शुरू हुआ और आज भी दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय और आम है। अब तो भारत में पुरस्कार गली और मोहल्ले के लोगों को भी दिए जाने लगे हैं। शायद इसकी एक वजह पुरस्कारों की लोकप्रियता है या पुरस्कारों का गिरता हुआ स्तर। पहले साल-दर-साल कुछ खास पुरस्कार पाने वालों का नाम सुना जाता था। लेकिन अब तो हर दिन किसी न किसी को पुरस्कार दिए जाने की खबर सुनाई देती है। कुछ साल पहले दिल्ली में एक मशहूर अखबार के रेज़िडेंट एडिटर ने अपनी निजी दोस्ती के आधार पर एक विदेशी उर्दू बोलने वाली महिला को पुरस्कार दिया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा। ऐसा लगता है कि उस विदेशी महिला को पुरस्कार देने का फैसला काफी जल्दबाज़ी में लिया गया था। सोशल मीडिया पर लोगों का यह भी कहना है कि दिल्ली के एक मशहूर अखबार से जुड़े साहब ने अपनी निजी दोस्ती के आधार पर उन्हें पुरस्कार दिलवाया।

थोड़ी देर के लिए अगर हम भारत और पाकिस्तान की मिसाल लें, तो हर दिन किसी न किसी को पुरस्कार दिए जाने की खबर मिलती रहती है। मुझे इससे हैरानी नहीं होती, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उस हिसाब से पुरस्कार हर दिन बाँटना ज़रूरी हो गया है। हालाँकि, आयोजकों को शायद यह आसानी ज़रूर हो गई है कि उन्हें पुरस्कार पाने वालों की योग्यता और क्षमता का बड़े पैमाने पर मूल्यांकन नहीं करना पड़ता और पुरस्कार आसानी से बाँट दिए जाते हैं।

इन सभी बातों के अलावा, दुनिया में कुछ संगठन अभी भी पुरस्कार देने का काम बखूबी कर रहे हैं और वे पुरस्कारों का स्तर भी बनाए रखे हुए हैं। तभी उनके पुरस्कार पाने वालों के नाम सुनकर कोई हैरानी नहीं होती और दिल खुश हो जाता है। इसके अलावा, पुरस्कार देने वाले संस्थान उस व्यक्ति के कारनामों और उसकी सफलता के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट या जानकारी प्रकाशित करते हैं, जिससे पुरस्कार पाने वालों के प्रति खुशी का इज़हार किया जाता है। इसके अलावा, मीडिया भी पुरस्कार के बारे में एक बेहतरीन और उच्च स्तर की रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिससे पुरस्कार और उसके पाने वालों के बारे में संतोषजनक जानकारी मिलती है। पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति के देश, परिवार, संस्थान और समाज में भी खूब जश्न मनाया जाता है।

हालाँकि, पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में यह खबर पढ़कर हैरानी के साथ-साथ अफसोस भी हुआ कि ट्रम्प को इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (जिनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हुआ है) ने एक पत्र देकर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया। बात यहीं खत्म नहीं होती, इससे पहले पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने भी अपने अमेरिकी दौरे के दौरान व्हाइट हाउस में ट्रम्प से मुलाकात करके उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अतीत में कई बार कहा कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जी, यह सुनकर आपके जैसे हमारे भी कान खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अरब-इज़रायल में अब्राहम समझौते जैसे शांति प्रयास किए और अन्य विवादों को कम करने में मदद की। वैसे, ट्रम्प साहब को याद दिलाया जाए कि ग़ज़ा में हज़ारों बच्चों और महिलाओं को इज़रायली सेना द्वारा मारने में अमेरिकी हथियारों का खूब इस्तेमाल हुआ। सोने पर सुहागा यह कि ट्रम्प को नामांकित करने वालों में एक महत्वपूर्ण नाम बेंजामिन नेतन्याहू का है, जिन्हें आईसीसी कोर्ट ने युद्ध अपराधों, निर्दोष नागरिकों पर हमले, भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और मानवाधिकार उल्लंघन के आधार पर वारंट जारी किया है। यानी ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए कैसे-कैसे लोगों के तलवे चाटने पड़ रहे हैं।

आइए, आपको बताते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन कौन करता है। अलग-अलग संस्थान हर साल हर श्रेणी में पुरस्कार देते हैं। छह में से पाँच का चयन स्वीडन में होता है। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का चयन नॉर्वे की नोबेल कमेटी करती है। यह कमेटी पाँच लोगों की होती है, जिन्हें नॉर्वे की संसद चुनती है। विशेषज्ञ, शिक्षाविद, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वैज्ञानिक, पूर्व विजेता और राष्ट्रीय सरकारों के सदस्य, ये सभी उन लोगों के नाम जमा करने के लिए अधिकृत हैं, जिन्हें वे शांति पुरस्कार जीतने के योग्य मानते हैं। इस साल ३४३ उम्मीदवार थे, जिनमें २५१ व्यक्ति और ९२ संगठन थे। लेकिन हमेशा की तरह, यह खुलासा नहीं किया गया कि शॉर्टलिस्ट में कौन है। नोबेल पुरस्कार वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा रखता है और विजेता को १० मिलियन स्वीडिश क्रोना या (:८०३,०००) ब्रिटिश पाउंड की पुरस्कार राशि दी जाती है।

१८९५ में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत मशहूर स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और चिकित्सा (फिजियोलॉजी) के विशेषज्ञों को दिया जाता है। हालाँकि, १९६८ में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की भी शुरुआत की गई। पुरस्कार का फैसला स्वीडिश अकादमी के विशेषज्ञ सदस्य करते हैं। हर साल १० दिसंबर को स्वीडन में एक विशेष समारोह होता है, जिसमें पुरस्कार विजेता अपना व्याख्यान पढ़ते हैं और पुरस्कार ग्रहण करते हैं।

तो यहाँ सवाल यह है कि क्या नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का दबाव होगा? संभव है, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार जैसी प्रतिष्ठित वैश्विक पहचान का अगर राजनीतिक, निजी या विवादास्पद उद्देश्यों के लिए उपयोग हो, तो यह न केवल इस पुरस्कार की अहमियत को ठेस पहुँचाता है, बल्कि दुनिया भर में शांति, न्याय और नैतिक नेतृत्व पर से भरोसा भी कमज़ोर हो जाता है। वैसे, नोबेल पुरस्कार की नींव अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत पर रखी गई थी, जिन्होंने स्पष्ट लिखा था कि शांति पुरस्कार उस व्यक्ति या संगठन को दिया जाए, जो राष्ट्रों के बीच भाईचारा, सशस्त्र बलों की कमी या शांति सम्मेलनों के प्रचार के लिए उल्लेखनीय काम करे। खैर, यह तो वसीयत है, तो नोबेल पुरस्कार की अवमानना कैसे हो सकती है? अगर पुरस्कार राजनीतिक प्रभाव या किसी विशेष शक्ति के दबाव में दिया जाए। या किसी विवादास्पद व्यक्ति, जिस पर युद्ध अपराध या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हों, या नैतिक विरोधाभास हो, उसे शांति पुरस्कार दिया जाए।

अगर इतिहास का अध्ययन करें, तो पता चलता है कि अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को १९७३ में वियतनाम युद्ध के दौरान शांति पुरस्कार मिला, हालाँकि उन पर लाखों मौतों में भूमिका का आरोप था। इस बात से नाराज़ होकर नोबेल कमेटी के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। अब अगर डोनाल्ड ट्रम्प जैसे विवादास्पद व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया, तो यह सिर्फ़ एक दुखद बात नहीं होगी, बल्कि नैतिक स्तर के पतन का प्रतीक भी होगी। जब शांति जैसे महान विचार को स्वयं शांति के रक्षक अपने हितों के लिए इस्तेमाल करें, तो दुनिया में न्याय की उम्मीद कमज़ोर हो जाती है। सच्चाई और झूठ का फर्क धुंधला हो जाता है और युवा पीढ़ी का भरोसा टूट जाता है।

मैं पुरस्कार पाने वालों की बहुत कद्र करता हूँ, क्योंकि इससे उस व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता का फल मिलता है और उसे एक सम्मान और रुतबा भी मिलता है। लेकिन मैं इस बात से भी चिंतित हूँ कि कुछ स्वार्थी और पूँजीपतियों ने पुरस्कारों का स्तर गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसके कारण दुनिया भर के लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर सदियों पुरानी परंपरा को नामी-नकामी स्वार्थी और पूँजीपति क्यों बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हर समझदार इंसान ऐसे नामी-नकामी और स्वार्थी लोगों को अपनी ईमानदारी और सच्चाई से ऐसा मुँहतोड़ जवाब देगा कि शिक्षित और योग्य लोगों, जो पुरस्कार पाने के हकदार हैं, उनकी प्रतिष्ठा को और ठेस न पहुँचे और पुरस्कारों का सम्मानजनक सिलसिला चलता रहे।

फहीम अख्तर, लंदन

वक्फ बोर्ड में पारदर्शी कार्यप्रणाली को प्राथमिकता

बाणेर मामले में उस समय के कानून का पालन, केवल बदनामी, कोई ठोस सबूत नहीं...!

अध्यक्ष समीर काझी का स्पष्ट रुख

सीएसनगर (औरंगाबाद) (प्रतिनिधि)

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड का कार्य पारदर्शी और गतिशील बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पुणे के बाणेर जमीन बिक्री का मामला २०१३ से पहले के कानून के अनुसार किया गया था। इस मामले में किसी भी सक्षम न्यायालय में मुतवल्ली विवाद, निर्णय या स्थगन नहीं है। फिर भी, मीडिया में हमारी बदनामी की जा रही है। गैर-व्यवहार का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। हम उचित जांच करके कानूनी कार्रवाई करेंगे, यह स्पष्ट रुख राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काझी ने रखा। शहर विस्तारीकरण और विकास योजना में शामिल होने वाली वक्फ जमीनों के संबंध में २ अगस्त को विभागीय आयुक्त और जिल्हाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। यह जानकारी उन्होंने पत्रकार परिषद में दी।

नया कानून भी काम नहीं रोक सकता

नया केंद्रीय कानून लागू होने के बावजूद, कोर्ट के आदेश से सदस्यों की नियुक्ति, वक्फ बाय यूजर और वक्फ कौंसिल जैसे मुद्दों को छोड़कर हम काम जारी रखेंगे। काम को रोका नहीं जा सकता, अन्यथा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संपत्तियों का पंजीकरण एक महत्वपूर्ण विषय है। ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। इस बारे में हमने केंद्रीय अल्पसंख्यक सचिव से चर्चा की है, जल्द ही इसका समाधान निकलेगा। वक्फ जमीनों के विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। राज्य में तंटामुक्त समितियां होनी चाहिए, यह हमारी भूमिका है। ऐसा होने पर ही जमीनों का विकास संभव है। इसके लिए एनजीओ की मदद से राज्यभर में शिविर आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में अकोला में जमीयत उलेमा की मदद से मुतवल्ली कार्यशाला आयोजित की गई थी।

बॉक्स

बाणेर मामले में गलतफहमी, किसी भी कोर्ट में मामला रद्द नहीं - जुनेद सय्यद

पुणे के बाणेर जमीन बिक्री मामले में

गलतफहमी के कारण यह सामने आए। संपत्ति का पंजीकरण २००५ में हुआ था और २००६ में जिल्हाधिकारी के बाजार मूल्यांकन के अनुसार ९.५१ करोड़ में बिक्री हुई। राशि मस्जिद के खाते में जमा की गई। २०१३ से पहले वक्फ बोर्ड की अनुमति से जमीन बिक्री का प्रावधान कानून में था। हालांकि, २०१३ में यह प्रावधान रद्द कर दिया गया। वर्ग-१, २ का मुद्दा बाद का है। इस मामले में किसी भी सक्षम न्यायालय ने इस करार को रद्द नहीं किया और न ही स्थगन दिया। इसलिए, दुर्भाग्यवश बिक्री करार की जांच किए बिना और गलतफहमी के कारण ही मीडिया में यह मामला प्रस्तुत किया गया। समीर काझी ने भी कहा कि अगर किसी को यह गलत लगता है, तो वह सक्षम न्यायालय में जाए। केवल वक्फ बोर्ड की बदनामी न करे।

३००० मामलों के निपटारे के लिए लॉ एजेंसी

वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए हम अधिक पारदर्शिता और कानूनी निपटारा चाहते हैं, इसलिए एक लॉ एजेंसी को काम सौंपा गया है। इस एजेंसी के पास निपुण वकील हैं, जो कोर्ट में वक्फ की मजबूत पैरवी करेंगे। इससे वक्फ की जमीनें कानूनी रूप से सुरक्षित रहेंगी और अतिक्रमित जमीनों को मुक्त करने में मदद मिलेगी।

विकास कार्यों में गई वक्फ जमीनों का मुआवजा मिलेगा

राज्यभर में सड़कों, सरकारी इमारतों या अन्य कार्यों के लिए कई वक्फ जमीनें गई हैं। इसके लिए ५०० से ६०० करोड़ रुपये बकाया हैं। इस बारे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ हमारी पहली बैठक हो चुकी है। अगली बैठक में हम उन्हें बताएंगे कि कितनी जमीनें गईं और कितना निधि बकाया है। अंततः विकास कार्यों और सामाजिक उपयोग के लिए हमें बड़े निधि की आवश्यकता है। अजित पवार वित्तमंत्री होने के नाते बोर्ड को काफी मदद मिलेगी, ऐसी अपेक्षा उन्होंने व्यक्त की।

मारपीट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, जांच करेंगे

हज हाउस में दो दिवसीय बैठक के दौरान पहले दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण मारपीट की घटना सामने आई। इस पर अध्यक्ष काझी ने कहा कि यह घटना अत्यंत निंदनीय है और हमारे कार्यकाल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमने दोनों पक्षों को बुलाया था। इसमें सलीम मुल्ला नामक व्यक्ति ने बताया कि सामने वाले ने उन्हें मारपीट की। इस मामले की हम जांच करेंगे। इसमें वक्फ बोर्ड या सदस्यों का कोई लेना-देना नहीं है। ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया जाएगा। दो दिवसीय बैठक हज हाउस में आयोजित की गई थी। इस दौरान बोर्ड के सदस्य हसनैन शाकिर, एडवोकेट ए.यू. पठाण, एडवोकेट एस.ए. हाश्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद सय्यद, उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुशीर शेख और विशेष अधीक्षक खुशरो खान व वक्फ अधिकारी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने अल्पसंख्यक समाज की योजनाओं को गति देने के लिए बुलाई विशेष बैठक

माजी मंत्री नवाब मलिक और विधायक सना मलिकने तकनीकी समाधान के साथ प्रभावी मुद्दे उठाए

मुंबई (प्रतिनिधि):

राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने अल्पसंख्यक समाज की प्रगति के लिए आवश्यक संस्थागत, शैक्षणिक और आर्थिक योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विशेष बैठक आयोजित कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

इस बैठक में माजी मंत्री नवाब मलिक और युवा, जोशीली एवं समर्पित विधायक सना मलिक ने प्रभावी ढंग से ठोस प्रश्न और समस्याओं के तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए। बीड़ शहर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता सय्यद नबील उज़्ज़मा को, जो पिछले कई वर्षों से इस दिशा में सतत संघर्ष कर रहे हैं, इस बैठक के माध्यम से बड़ी सफलता मिली है।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में अल्पसंख्यक मंत्री दत्ताभरणे, वैद्यकीय शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी मंत्री नवाब मलिक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विधायक सना मलिक के माध्यम से आयोजित इस विशेष बैठक में मार्टी (अल्पसंख्यक संशोधन और प्रशिक्षण संस्था) से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों को उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने स्वीकार किया:

बैठक में स्वीकार की गई प्रमुख मांगें:

१. स्वायत्त संस्था के लिए स्वतंत्र लेखा शीर्षक (मुख्य) खोलने की प्रक्रिया शुरू करना।

२. कंपनी अधिनियम २०१३ के अंतर्गत संस्था का पंजीकरण कर स्वायत्त दर्जा देना।

३. मंजूर ११ पदों पर रुकी हुई भर्ती तुरंत शुरू करना।

४. छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) में अस्थायी कार्यालय शीघ्र शुरू करना।

५. मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के अंतर्गत अण्णासाहेब पाटील महामंडल की तर्ज़ पर ब्याजमुक्त कर्ज योजना तुरंत लागू करना।

६. मराठवाड़ा क्षेत्र में यूनानी हकीम की कुल २५ में से २१ रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत शुरू करना।

बैठक में मार्टी के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के लिए आवश्यक योजनाओं को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने का ठोस प्रयास किया गया।

अब लाभार्थियों को नहीं भरना होगा ब्याज

बीड़ शहर के सामाजिक कार्यकर्ता सय्यद नबील उज़्ज़मा लंबे समय से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए सतत संघर्ष कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से ब्याजमुक्त कर्ज योजना की उनकी मांग भी इस बैठक में स्वीकार की गई।

अब अण्णासाहेब पाटील महामंडल की तर्ज़ पर यह योजना तुरंत शुरू की जाएगी। लाभार्थियों को कर्ज बैंक के माध्यम से मिलेगा, लेकिन उस पर लगने वाला ब्याज सरकार मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से वहन करेगी।

संघर्ष की ताक़त से अल्पसंख्यक समाज को मिलेगा लाभ

सय्यद नबील उज़्ज़मा द्वारा वर्षों से अत्यंत निष्ठा और जज़्बे के साथ किया गया सतत प्रयास, विधायक सना मलिक और माजी मंत्री नवाब मलिक का सहयोग तथा संगठनात्मक रूप से लड़ा गया यह संघर्ष अब अल्पसंख्यक समाज की प्रगति में सहायक सिद्ध होगा - यह निश्चित है।

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल का

मराठवाड़ा उपविभागीय कार्यालय २७ जुलाई को बीड़ में होगा उद्घाटन

बीड़, दिनांक २४ (संवाददाता):

मराठवाड़ा में महामंडल की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए, अण्णासाहेब पाटील विकास फाउंडेशन के विशेष सहयोग से कार्यान्वित होने वाले अण्णासाहेब पाटील आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल के मराठवाड़ा उपविभागीय कार्यालय का उद्घाटन रविवार, २७ जुलाई २०२५ को सुबह ११ बजे यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, बीड़ में किया जाएगा। इस उद्घाटन के अवसर पर एक मेळावे (सभा) का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक नागरिकों को उपस्थित रहने की अपील महामंडल के विभागीय समन्वयक श्री प्रवीण आगवण पाटील ने की है।

इस उपविभागीय कार्यालय का मुख्य उद्देश्य मराठवाड़ा क्षेत्र में महामंडल की योजनाओं का प्रचार-प्रसार बढ़ाना है, ताकि समाज के पात्र मराठा लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। इसके साथ ही ई-सेवा केंद्र, उडउ केंद्र, निजी ऑनलाइन सेंटर अथवा एजेंटों के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सके।

महामंडल का प्रयास है कि अधिक से अधिक मराठा युवक उद्यमी बनें। इसके लिए बैंकों में लंबित कर्ज प्रकरणों से जुड़ी शिकायतों का निवारण, ब्याज वापसी की त्रुटियों का मार्गदर्शन, क्लेम होल्ड, सैंक्शन होल्ड आदि विषयों के लिए हेल्पलाइन सेंटर के ज़रिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मराठवाड़ा में शुरू होने वाला यह कार्यालय पूरी तरह से सुसज्जित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। पात्र लाभार्थियों को यहां महामंडल द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं की जानकारी और सहायता एक ही स्थान पर प्राप्त होगी। इससे समय की बचत होगी और आवेदन की प्रक्रिया भी सरल बनेगी। साथ ही, भविष्य में तालुका स्तर पर भी योजनाओं को पहुंचाने हेतु दौरे किए जाएंगे, यह जानकारी महामंडल के अध्यक्ष नरेंद्र पाटील ने दी। यह उपविभागीय कार्यालय राजू कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंज़िल, हिना होटल के सामने, जालना रोड, बीड़ में शुरू किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, बीड़ में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर नागरिकों से अपील की गई है कि वे बड़ी संख्या में शामिल होकर महामंडल की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और अपनी समस्याओं का समाधान भी करवाएं, ऐसा आह्वान श्री आगवण पाटील ने किया है।

बारिश जैसी मंत्रीमंडल फेरबदल की 'चर्चाओं की बौछार'!

मुख्यमंत्री फडणवीस की दिल्ली में अमित शाह से मंत्रिमंडल को लेकर खास बैठक

/ रिपोर्ट: जमीर काज़ी । मुंबई से

मुंबई :

राज्य में महायुती सरकार के कुछ मंत्रियों के विवादित बयानों और बर्ताव के कारण लंबे समय से मंत्रीमंडल में बदलाव की चर्चाएं तेज़ हैं। कुछ मंत्रियों को हटाने और कुछ के विभागों में फेरबदल कर सरकार की छवि साफ करने का निर्णय महायुती के तीनों घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। यह चर्चा ठीक उसी तरह ज़ोर पकड़ रही है जैसे मानसून की मूसलाधार बारिश।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस विषय में चर्चा की। सूत्रों के अनुसार, करीब ३० मिनट तक चली बैठक में फडणवीस ने विवादास्पद मंत्रियों को हटाने की सिफारिश की, जिस पर शाह ने सहमति जताई और 'हरि झंडी' दिखाई।

संभावित फेरबदल की सूची में ये नाम:

कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

शिक्षा मंत्री दादा भुसे

गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

इन मंत्रियों के या तो विभाग बदले जाएंगे या उन्हें मंत्रीमंडल से बाहर किया जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है।

विवादों की झड़ी:

मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह कथित तौर पर नग्न अवस्था में नोटों से भरी बैग के साथ बेडरूम में दिखाई दिए।

कृषि मंत्री कोकाटे का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान मोबाइल पर रमी खेलते दिखे।

गृह राज्यमंत्री योगेश कदम की मां जयश्री कदम के नाम पर एक 'सावली डांस बार' चलने का मामला भी सुर्खियों में है।

इन घटनाओं ने सरकार की छवि को भारी नुकसान पहुँचाया है। विपक्ष ने इन मामलों पर तीखे हमले किए हैं। यद्यपि सरकार और संबंधित मंत्रियों ने सफाई दी है, लेकिन जनता में नाराज़गी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इन मामलों को लेकर नाराज़गी जताई है और अपने दल के साथ-साथ उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी अपने-अपने मंत्रियों को उचित चेतावनी देने को कहा है।

फेरबदल की योजना:

सरकार की छवि स्वच्छ बनी रहे, इसीलिए जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। कुछ मंत्रियों को 'नारियल' यानी विदाई दी जाएगी, जबकि कुछ के विभाग बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने दो दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान इसी पर उच्च स्तर पर चर्चा की है।

संजय राऊत का बड़ा दावा:

ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राऊत ने दावा किया है कि:

महायुती सरकार के ८ विवादास्पद मंत्रियों को जल्द हटाया जाएगा।

उनकी जगह कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मंत्री पद दिया जाएगा और उनकी जगह वरिष्ठ विधायक सुधीर मुनगंटीवार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा।

इन ८ मंत्रियों में २ भाजपा, ४ शिंदे गुट, और २ अजित पवार गुट के मंत्री शामिल हैं।

शाह-फडणवीस की 'गुप्तगू':

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच दिल्ली में लगभग आधा घंटा बंद कमरे में बैठक हुई। इसमें विवादित मंत्रियों को हटाने पर गंभीर चर्चा हुई।

यह फेरबदल न केवल सरकार की छवि सुधारने का प्रयास है, बल्कि आगामी चुनावों से पहले जनता में अच्छा संदेश देने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।

बीड तहसीलदार चंद्रकांत शेलके साहब का राष्ट्रीय कांग्रेस निराधार निराश्रित विभाग की ओर से सम्मान समारोह संपन्न

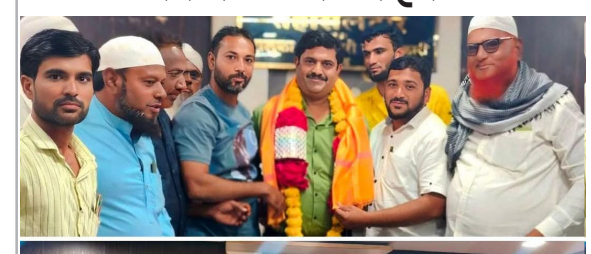

/ शेख मोहसिन की रिपोर्ट

बीड:

राष्ट्रीय कांग्रेस के राज्यसभा सांसद माननीय रजनी ताई अशोक राव पाटील और राष्ट्रीय कांग्रेस बीड जिला अध्यक्ष राहुल भैय्या सोनवणे के मार्गदर्शन में, बीड तहसीलदार श्री चंद्रकांत शेलके साहब को उनके छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) में शासकीय सेवा के दौरान कर्तव्यनिष्ठ कार्य के लिए 'मराठवाड़ा आइकॉन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

इस गौरवपूर्ण अवसर पर बीड शहर में राष्ट्रीय कांग्रेस निराधार निराश्रित विभाग की ओर से बीड जिला अध्यक्ष शेख मोहसिन और बीड तालुका अध्यक्ष शेख जहीर आमिर ने चंद्रकांत शेलके साहब का औपचारिक सत्कार (सम्मान) किया।

इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित थे:

सय्यद सादिक सय्यद रियासत

राष्ट्रीय कांग्रेस निराधार निराश्रित विभाग के कार्याध्यक्ष जमील खान सत्तार खान तालुका उपाध्यक्ष सय्यद तोफिक तांबोळी

शेख मुकद्दर, सय्यद मसलोद्दीन, सय्यद इरफान, अझर खान, शेख समीर आदि गणमान्य लोग।

कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें श्री शेलके साहब को उनके समर्पित प्रशासनिक कार्य के लिए सराहा गया।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com